SHORT DURATION DISCUSSION

Steep rise in prices of essential commodities—*Contd.*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Shrimati Kamla Sinha — last speaker. Madam, you will agree that democracy requires that you should also be brief.

SHRIMATI KAMLA SINHA (Bihar): I will be very brief.

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही उचित बात है कि राज्य सभा में महंगाई के ऊपर विचार हुआ, डिसकशन हुआ और सभी सदस्यों ने चाहे वे इधर के हों या उधर के हों, बहुत चिंता व्यक्त की है । महंगाई के ऊपर काबू पाना चाहिये, यह उचित बात है । लेकिन अगर हम बुनियादी बातों पर जायेंगे तो पता चलेगा कि यह महंगाई एक दिन में नहीं बढ़ी है । इसका कारण यह है कि पिछले वर्षों में जिस ढंग से सरकार चलाई गई थी और जिस तरीके से विदेशों से पैसा उधारखाते में लिया गया और जिस तरह से इस देश में ऐशो आराम के साथ राज चलाया गया उसका नतीजा यह हुआ कि डेफिसिट फाइनेंसिंग बढ़ता ही गया और डेफिसिट फाइनेंसिंग के कारण महंगाई बढ़ती चली गई । हमारी सरकार जब आई तो हमारे वित्त मंत्री ने बारम्बार कहा कि हमें खजाना बिल्कुल खाली मिला । डेफिसिट फाइनेंसिंग किसी भी देश के लिये खतरनाक होता है । इसका उदाहरण हमारे सामने लेटिन अमेरिका देश हैं और दुनिया के कुछ अन्य देश भी हैं । हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा काम किया और उन्होंने डेफिसिट फाइनेंसिंग को पाटने की कोशिश की और जो प्रति दिन बढ़ रहा था उसको 11 हजार करोड़ से साढ़े 7 हजार करोड़ तक ला दिया । उसका नतीजा यह हुआ कि चीजों के दाम बढ़ने लगे । अपने देश से पैसा उगाना आवश्यक था । इससे भी चीजों के दाम बढ़ने लगे । यह बात भी सत्य है कि अगर किसी एक चीज के दाम बढ़ते हैं तो उसका इम्फेक्ट दूसरी चीजों पर भी पड़ता है । पेट्रोल के दाम बढ़े तो रिक्शे के दाम भी बढ़ गये, उसका किराया बढ़ गया । रिक्शा पेट्रोल से नहीं चलता है लेकिन फिर भी किराया बढ़ गया । किसी भी वेलफेयर स्टेट में उपभोक्ता चीजों को ठीक दाम पर खरीद सकें यह उद्देश्य होता है । अगर कीमतें बढ़ती हैं तो उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ जाती है । आज वही स्थिति है । इसका क्या कारण है ? हमारी सरकार की जो पालिसी है वह मुनाफाखोरों और ट्रेडर्स को पसन्द नहीं है । उन्होंने जमा करना शुरू कर दिया और जमाखोरी के कारण चीजों के दाम बढ़ने लगे । उदाहरण के लिये मैं बताना चाहती हूं कि फरवरी महीने में सीमेंट का एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या था ? मैं बिहार से आती हूं, वहां के कारखानों के बारे में जानती हूं । वहां कई जगह के यूनियनों से मेरा संबंध है । कल्याणपुर सीमेंट का एक्स फैक्ट्री दाम पहले 62 रुपया प्रति बोरा था, वह 65 रुपया का हो गया और यह 28 फरवरी तक रहा । लेकिन मार्च में यह 75 रुपया हो गया और अप्रैल में पटना के बाजार में यह 105 रुपया हो गया । उसकी कोई लागत नहीं बढ़ी, रॉ-मेटिरियल की कीमत नहीं बढ़ी, मजदूरों को कोई ज्यादा पैसा नहीं दिया गया, फिर भी कीमत बढ़ा दी गई । यह मैंने आपको एक उदाहरण दिया है । वही हालत खाद्य तेलों की है । पिछले साल अच्छी बारिश हुई और एडाबल आयल जो चिनिया बादाम से बनता है और जो गुजरात में पैदा होता है उसकी अच्छी उपज हुई तो उसके दाम घट गये । यह भी सही है कि इस साल हम थोड़ी परेशानी में हैं । जो हमारे पूर्वी प्रांत है जहां पर सरसों की उपज होती है वह कुछ कम हुई है । आज भी खेती के लिये हमें आकाश की ओर देखना पड़ता है । खेती के मामले में किसानों को और भी परेशानियां होती है जैसे कि कीड़ा लग गया अगर सरसों में कीड़ा लग जाय तो उसके कारण सरसों की उपज कम होती है । सरसों के तेल के दाम कम से कम बिहार प्रांत की बात मैं जानती

[श्रीमति कमला सिंहा]

हूं, वहां बहुत बढ़े हुये हैं 25-26 रुपये किलो पर बिक रहा है। दूसरी जगहों पर भी यही हालत है। क्योंकि हमारे देश में फारेन एक्सचेंज रिजर्व कम है, इसलिये हमारी सरकार ने कहा कि हम तेल बाहर से नहीं मगायेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, विदेशी मुद्रा की कमी है। इस का लाभ उठाकर व्यापारियों ने दाम बढ़ा दिये हैं। मेरा वित्त मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस प्वाइंट के ऊपर सरकार को पुनः विचार करना चाहिये। किसी भी वेल फेयर स्टेट को सरकार का प्रथम दायित्व है कि वह उपभोक्ताओं को, और देश के लोगों को सही दाम पर सामान मुहैया करवाये। बड़े लोगों के लिये नहीं बल्कि जो साधारण लोग है उनके लिये कम से कम सरकार को यह करना ही होगा। इसलिये उनके लिये तेल के मामले में सरकार को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिये और अगर आवश्यक समझे तो बाहर से तेल मंगाये ताकि तेल के दाम कम हो सकें।

दूसरी बात मैं चीनी के बारे में कहना चाहूंगी। चीनी के बारे में यहां पर बहुत चर्चा हुई है। यह आवश्यक है कि चीनी की नीति हम लोगों को बदलनी चाहिये। पहले हम विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये चीनी कम दामों पर बाहर भेजते थे **(समय की घंटी)** दो मिनट।..और अपने यहां चीनी ज्यादा दामों में बेचते थे। अब इस पालिसी को चेंज करना ही होगा। वेलफेयर स्टेट का प्रथम कर्तव्य होता है कि सर्वप्रथम अपने देश की जरूरत को पूरा करना। अगर यहां चीनी की आपूर्ति पूरी हो जाय और उसके बाद अगर फालतू चीनी बचे तो निश्चित रूप से आप उसको बाहर के बाजारों में बेचें। इसी तरह से जो अन्य सामग्री हम पैदा करते हैं सब्जी, फल, प्याज वगैरह, अब भी हम इन चीजों को बाहर भेजते हैं तो अपने देश में बाजार में इन चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिये। मूल्यों पर नियंत्रण पाना अति आवश्यक है। इसको यथाशीघ्र करें नहीं तो फिर हम लोगों को बहुत परेशानी होगी, आम लोगों को तो परेशानी हो ही रही है। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Hon. Members, the discussion on this topic concludes now. The Minister will reply tomorrow.

The ouse is adjourned till eleven o'clock on the 17th May, 1990.

The House then adjourned at fifty-three minutes past six of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 17th May, 1990.